

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या: 322 /XXXVI(1) (एक)/2009-33-एक(4)/2004

देहरादून दिनांक : 09 दिसम्बर, 2009

अधिसूचना

विविध

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तरप्रदेश लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों) नियमावली, 1991 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में और संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का प्रतिस्थापन 2. उत्तरप्रदेश लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों) नियमावली, 1991 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ 1

वर्तमान नियम

3. वेतन— अध्यक्ष तीस हजार रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करेगा, उपाध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करेगा और सदस्य 22400—525—24500 रुपये के वेतनमान में प्रतिमाह वेतन प्राप्त करेगा ;

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो या जो केन्द्र या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ हो, वेतन ऐसी सेवा निवृत्ति के समय उसे भुगतान किये गये या देय वेतन से कम नहीं होगा ;

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के किसी लाभ को प्राप्त करता है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो उसके उपर्युक्त वेतन से पेंशन की सकल राशि को, जिसमें व्यक्ति की सरांशीकृत पेंशन का भाग, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, कम कर दिया जायेगा ।

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3. वेतन— उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रवृत्त होने के बाद नियुक्त होने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो या जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ हो, नियत वेतन ऐसी सेवानिवृत्ति के समय उसे भुगतान किया गया या देय वेतन होगा ;

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, जो पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के किसी लाभ को प्राप्त करता है या प्राप्त किया है, तो उसके उपर्युक्त वेतन से, पेंशन की सकल राशि को, जिसमें व्यक्ति की सरांशीकृत पेंशन का भाग, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, कम कर दिया जायेगा ;

परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व की तिथि पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्यरत व्यक्ति को उसके इस रूप में अवशेष कार्यकाल की अवधि तक उसे तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत वेतन से राशिकरण के पूर्व पेंशन, घटाकर वेतन मिलता रहेगा ।

नियम 7 का प्रतिस्थापन 3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ 1

वर्तमान नियम

7. पेंशन (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त अधिकरण का प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई पेंशन देय नहीं होगी—

(एक) यदि उसने दो वर्ष से कम की सेवा की हो, या

(दो) यदि उसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन अधिकरण में किसी पद से हटा दिया गया हो ।

(2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके भाग के लिये सात सौ रुपये प्रतिवर्ष की दर से की जायेगी और अधिकरण में चाहे जितने वर्ष की सेवा हो, पेंशन की अधिकतम धनराशि तीन हजार पांच सौ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी;

परन्तु इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को देय पेंशन की कुल धनराशि किसी पेंशन की धनराशि के साथ (जिसमें पेंशन का सरांशीकृत भाग भी है) यदि कोई हो जो उच्च न्यायालय के

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

7. पेंशन (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त अधिकरण का प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई पेंशन देय नहीं होगी—

(एक) यदि उसने दो वर्ष से कम की सेवा की हो, या

(दो) यदि उसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन अधिकरण में किसी पद से हटा दिया गया हो ।

(2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके भाग के लिये सात सौ रुपये प्रतिवर्ष की दर से की जायेगी और अधिकरण में चाहे जितने वर्ष की सेवा हो, पेंशन की अधिकतम धनराशि तीन हजार पांच सौ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी;

परन्तु इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को देय पेंशन की कुल धनराशि किसी पेंशन की धनराशि के साथ (जिसमें पेंशन का सरांशीकृत भाग भी है) यदि कोई हो, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सरकारी सेवक के

न्यायाधीश या सरकारी सेवक के रूप में अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा की गयी सेवा के सम्बन्ध में उसे अनुमन्य हो वह उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या भारत सरकार के किसी सचिव को अनुमन्य पेंशन की अधिकतम धनराशि, इसमें जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी ।

रूप में अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा की गयी सेवा के सम्बन्ध में उसे अनुमन्य हो वह उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या भारत सरकार के किसी सचिव को अनुमन्य पेंशन की अधिकतम धनराशि, इसमें जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी ।

(3) उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रवृत्त होने के बाद नियुक्त होने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य पेंशन के हकदार नहीं होंगे ।

नियम 8 का प्रतिस्थापन 4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा , अर्थात्-

स्तम्भ 1

वर्तमान नियम

8. भविष्य निधि (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य सामान्य भविष्य निधि में अपने विकल्प पर अंशदान करने के लिये हकदार होंगे और इस प्रकार विकल्प करने की दशा में जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे ;

परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

8. भविष्य निधि (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य सामान्य भविष्य निधि में अपने विकल्प पर अंशदान करने के लिये हकदार होंगे और इस प्रकार विकल्प करने की दशा में उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे;

परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था या

या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य था, तो वह उन नियमों द्वारा शासित होगा जो उस पर अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व प्रयोज्य थे ।

अखिल भारतीय सेवा का सदस्य था, तो वह उन नियमों द्वारा शासित होगा जो उस पर अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व प्रयोज्य थे ;

परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रवृत्त होने के बाद नियुक्त होने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के सम्बन्ध में भविष्य निधि की व्यवस्था लागू नहीं होगी ।

आज्ञा से,
Arundhati
(आर0डी0पालीवाल)
सचिव

संख्या: (1) /XXXVI(1) (एक)/2009-33-एक(4)/2004तददिनांक ।

प्रतिलिपि- निदेशक, लिथो राजकीय प्रेस, रुड़की को उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009 की हिन्दी व अंग्रेजी की प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया इन्हें गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुये अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

(आर0 डी0 पालीवाल)
सचिव

संख्या: 322 (2) /XXXVI(1) (एक)/2009-33-एक(4)/2004तददिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।

- 2- अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा प्राधिकरण, 316, फेज-1, बसन्त बिहार, देहरादून।
- 3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

medatiraf
(आर0 डी0 पालीवाल)
सचिव